an>

Titl: Need to increase the Central Government assistance under Coastal Security Scheme.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल **(मेहसाणा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी के अन्तर्गत फेज़-टू मंजूर किया गया है, जिसका मूलभूत उद्देश्य राज्यों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की परिपूर्ति करने का है। इस फेज टू के तहत गुजरात राज्य को मरीन पुलिस स्टेशन, 31 इंटर सैक्टर बोर्ड औऱ 5 जेटीज के लिए वाहन आबंटित किये गये हैं। फेज टू अप्रैल 2011 से प्रारंभ किया गया है तथा फेज वन पूर्ण करने में गुजरात राज्य देश में अग्रसर है। फेज वन में आबंटित की गई 30 बोटों को लगाने के लिए अतिरिक्त जेटी उपलब्ध नहीं है। एक मैरीन पुलिस स्टेशन में दो तीन बोट्स आबंटित की गई हैं जिसके कारण पैट्रोलिंग रूट के नजदीक बोट को खड़ा करने के लिए जेटी की अत्यंत जरूरत है। बोट को खड़ा करने के लिए आज तक जेटी के निर्माण के लिए उचित वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित नहीं की गई है। पांच जेटी के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ढ़ाई करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। एक जेटी के लिए पचास लाख रुपये भी अपर्याप्त है। एक जेटी के निर्माण के लिए मिनिमम पांच करोड़ रुपये की जरूरत होती है।

मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम के तहत राज्य में जेटी के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।